







# विद्या

## न जाने दोस्त कब दुश्मन बन जाये?

प्रधानमंत्री मोदी ने शेक्सपियर को पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने शेक्सपियर के शब्दों में सच्चाई को जरूर आत्मसात किया है—“दोस्ती में चापलूसी होती है” अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चापलूसी करते हुए, नरेंद्र मोदी आप्रवासन और निर्वासन, बीजा, व्यापार संतुलन, टैरिफ, परमाणु ऊर्जा, दक्षिण चीन सागर, ब्रिक्स, क्वाड और एफ.टी.ए. के मुद्दों पर बातचीत करने की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के पास 4 साल हैं, और इससे ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के पास 4 साल हैं और माना जाता है कि वे इससे ज्यादा चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि सभी मुद्दे 4 आम वर्षों में हल नहीं हो सकते। अगली अमरीकी सरकार-चाहे रिपब्लिकन हो या डैमोक्रेट-शायद ट्रम्प के रास्ते पर चलना न चाहे। यहीं भारत के लिए पहला सबक है। दो नेताओं के बीच व्यक्तिगत ‘दोस्ती’ से परे देखें।

इसके अलावा, जहां तक ट्रम्प का सवाल है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि दोस्त कब दुश्मन बन जाएगा और दुश्मन कब दोस्त बन जाएगा। भारत को नुकसान हो सकता है। मोदी ने पॉडकास्टर लैक्स फिडमैन को दिए एक साक्षात्कार में ट्रम्प की उनकी 'विनप्रता' और 'लचीलेपन' के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प 'पहले से कहीं ज्यादा तैयार थे' और 'उनके दिमाग में एक स्पष्ट रोडमैप है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित कदम हैं, जिनमें से प्रत्येक उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।' मोदी ने कहा, "मुझे सच में विश्वास है कि उन्होंने एक मजबूत, सक्षम समूह बनाया है और इतनी मजबूत टीम के साथ, मुझे लगता है कि वे राष्ट्रपति ट्रम्प के विजन को लागू करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सभी अमरीकी ट्रम्प की प्रशंसा से सहमत नहीं होंगे। सभी सीनेटरों और प्रतिनिधियों ने नहीं सोचा कि ट्रम्प द्वारा चुने गए सचिव सक्षम या मजबूत थे। सभी अमरीकी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ट्रम्प का विजन अमरीका या दुनिया के लिए अच्छा था। यदि ट्रम्प ने अपने दृष्टिकोण को लागू किया, तो यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। यदि ट्रम्प अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे तो इसका मतलब यह होगा कि अमरीका में अधिकांश अनिर्दिष्ट भारतीयों (अनुमानित 700,000) को भारत भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि कई भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों को अमरीकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि अधिकांश भारतीय-अमरीकी नागरिक अपने परिवारों को संयुक्त राज्य अमरीका नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि उच्च योग्यता वाले भारतीयों को जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा की संख्या में भारी कमी आएंगी। इसका मतलब यह होगा कि भारत को हार्ले-डेविडसन बाइक, बॉर्बन व्हिस्की, जींस और अन्य अमरीकी सामानों पर टैरिफ कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

# टीवी के खिलाफ जंग को करना होगा तेज़

भारत काफी लंबे समय से टीबी नामक बिमारी से जंग लड़ रहा है। लेकिन अब टीबी को लेकर एक डरावनी स्टडी सामने आई है। जर्नल प्लस मेडिसिन की स्टडी के मुताबिक भारत में अनुमान है कि 2021 से 2040 तक टीबी के 6 करोड़ केस और 80 लाख मौतें हो सकती हैं। स्टडी के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत कमी के लक्ष्य से बहुत कम है। इसी प्रकार टीबी से संबंधित मौतें में 75 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले केवल 24 प्रतिशत की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर 2023 में 82 लाख लोगों में टीबी के नए मामलें देखे गए।

मुताबिक भारत को इस बिमारी के चलते न सिर्फ जान का नुकसान होगा बल्कि सकल धरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 146 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान होने की संभावना है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन यूके के रिसर्चर ने कहा कि इसके चलते कम आय वाले मिडिल क्लास परिवार ज्यादा संकट में हैं। उनको स्वास्थ्य संबंधी बोझ झेलना पड़ सकता है। जबकि अपरीर परिवारों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूचिएचओ) ने वैश्विक क्षय रोग (टीबी) रिपोर्ट 2024 जारी किया है। जिसमें 2024 में दुनिया की 99 प्रतिशत से अधिक आबादी और टीबी के मामलों वाले 193 देशों के डाटा की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट वैश्विक, क्षत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी एवं रोग की रोकथाम, निदान और उपचार सेपता है। इस बानी पर यह इराजा तो है जरात लाना नियमित रूप से दवा लें। हर वर्ष 24 मार्च को पूरे विश्व में टीबी (विश्व क्षय रोग) दिवस मनाया जाता है। इस दिन टीबी यानि तपेदिक रोग के बारे में लोगों को जागारूक किया जाता है। भारत में बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रही है। देश में जब तक गरीबी दूर नहीं होगी तब तक टीबी पर पूर्णतया रोक नहीं लगा पायेगी।

महानाराय एवं राण का राक्षयम, निदान जार उपचर में प्रगति का व्यापक व अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष के अनुसार 2023 में भारत में लगभग 25.2 लाख टीबी के मामले सामने आये थे। जो 2022 में 24.2 लाख मामलों से अधिक थे। भारत और इंडोनेशिया में वर्ष 2021 से 2023 तक टीबी के वैश्विक मामलों में कुल वृद्धि 45 प्रतिशत थी। दुनिया के पांच देश भारत, इंडोनेशिया चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान में टीबी के कुल वैश्विक मरीजों के 56 प्रतिशत थे।

भारत में वर्ष 2015 से 2023 के मध्य टीबी के मामलों में 18 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह

# एक वृहद् धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाए जाने की जरूरत

वी-डेम इंसिट्यूट की भारत के संबंध में रपट, जो द हिंदू में प्रकाशित की गई है, में कहा गया है कि यह रेखांकित करते हुए कि लोकतंत्र के लगभग सभी घटकों की स्थिति जितने देशों में सुधर रही है, उससे अधिक देशों में बिगड़ रही है, रपट में विशेष तौर पर यह जित्र किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव और संगठित होने व नागरिक समाज की आजादी पर निरंकुशता की ओर बढ़ते देशों में सबसे गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा है। रपट में भारत के मैदानी हालात का काफी सटीक सार प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, भारत में अल्पसंयंकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हाल के समय में आरएसएस-बीजेपी मिलकर हिंदू उत्सवों और समागमों का इस्तेमाल अल्पसंयंकरों को आतंकित करने के एक और औजार के रूप में करने लगे हैं। यह रामनवमी के समारोहों, होली और कुंभ मेले के दौरान व्यापक तौर पर देखा गया।



पिछले दस सालों से सत्ता पर काबिज समूह के बढ़ते हुए तानाशाहीपूर्ण रवैये के चलते ही तमाम विरोधाभासों के बावजूद अधिकांश विपक्षी दलों के एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के गठन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा व सामाजिक समूहों द्वारा गठित मर्मचों जैसे इदिलू कर्नाटका और भारत जोड़ो अभियान का मिलाजुला प्रभाव लोकसभा चुनावों पर पड़ा और भाजपा का 400 सीटें जीतने का लक्ष्य मिट्टी में मिल गया। यह सच है कि इंडिया गठबंधन वांछित दिशा में नहीं बढ़ा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का इरादा पूरा न हो सका। यह इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र और हारियाणा चुनावों में सफलता हासिल न हो पाने की एक वजह थी। इसकी दूसरी वजह थी संघ परिवार के सभी सदस्यों द्वारा भाजपा के पक्ष में पूरी ताकत लगा देना। यह कोई नई बात नहीं है लेकिन यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनावों के दौरान जे। पी। नड्डा ने बयान दिया था कि भाजपा को आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वह इतनी सशक्त हो गई है कि सिफ अपने दम पर चुनाव जीत सके। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण जरूरत के प्रति उसके कई घटक दलों का रवैया उपेक्षापूर्ण रहा और कई ने इसके प्रति उदासीनता दर्शाई और सबसे बड़े विपक्षी दल, कांग्रेस ने भी इस संबंध में कोई बड़ी पहल नहीं की। यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारधारा की दृष्टि से इस गठबंधन का सशक्त घटक सीपीआई (एम) इस मामले पर पुनर्विचार कर रहा है। उसके कार्यवाहक महासचिव प्रकाश करात ने कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था राज्यों के चुनावों के लिए नहीं।। और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों का एक वृद्ध गठबंधन बनाए जाने का आव्हान किया।

उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधनों को एक वृद्ध परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ताकि चुनावी राजनीति उनका गला न घोंट दे। यही बात दूसरे शब्दों में वामपंथी द्वाकावाले बुद्धिजीवी कह रहे हैं जिनका मानना है कि भाजपा दरअसल, एक पूरी तरह फासीवादी पार्टी नहीं है। जैसे प्रभात पटनायक तर्क देते हैं कि जहां नवउदारवादी पूंजीवाद एक 'फासीवादी हालात' उत्पन्न करता है जो दक्षिणपंथी अधिनायकवादी आंदोलनों, विदेशियों के प्रति द्वेष, अति राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षय के रूप में प्रकट होती है। किंतु यह अनिवार्यतः 1930 के दशक के पूरी तरह से 'फासीवादी राष्ट्र' का पुनर्सृजन नहीं करती।'

हिन्दुत्वादी राष्ट्रवाद के लिए नव फासीवाद, आद्य फासीवाद, कट्टरवाद आदि कई शब्दों का इस्तेमाल किया

पासापाद, काटृपाद ऊपर पाइ राष्ट्रा पा इसामारा विवाह

गया है परंतु रेखांकित करने वाली बात यह है कि कोई भी राजनैतिक परिघटना स्वयं को उसी तरीके से नहीं दुरहारी। आज हिन्दुत्वादी राष्ट्रवाद के कई लक्षण फासीवाद से मिलते-जुलते हैं। फासीवाद ही आरएसएस के संस्थापकों, विशेषकर एम। एस। गोलवलकर का प्रेरणास्रोत था। उन्होंने अपनी पुस्तक “वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड” में कहा अपनी संस्कृति और नस्ल की शुद्धता कायम रखने के लिए जर्मनी ने सेमेटिक नस्लों - यहूदियों - का देश से सफाया कर दुनिया को आश्वर्यचिकित कर दिया। यह नस्लीय अभिमान की उच्चतम अभिव्यक्ति है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि मूलभूत अंतर वाली विभिन्न संस्कृतियों और नस्लों का मिलकर एक हो जाना लागभग असंभव होता है। यह हिन्दुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं।

हम भारत में फासीवाद के लक्षणों को उभरता देख रहे हैं जैसे स्वर्णिम अतीत, अखंड भारत की अभिलाषा, अल्पसंख्यकों को देश का शत्रु करार देकर निशाना बनाना, अधिनायकवाद, बड़े उद्योग-धंधों को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार और सामाजिक चिंतन पर हावी होना आदि। हम यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति असहनशीलता का नजारा देख रहे हैं, जैसा कि महात्मा गांधी के प्रपोत्र तुषार गांधी के मामले में हाल में हुआ। उन्होंने कहा था “आरएसएस एक जहर है। वे इस देश की अंतरात्मा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इससे भयभीत होना चाहिए क्योंकि यदि अंतरात्मा नष्ट हो जाती है, तो सब कुछ छिन जाता है।” तुषार गांधी से माफी मांगने और अपने शब्द वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया और अब उन्हें हत्या की धमकियाँ दी जा रही हैं।

आरएसएस ने अपनी जबरदस्त पहुंच, सैकड़ों अनुषांगिक संगठनों, हजारों प्रचारकों और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से आजादी के आंदोलन से जन्मे भारत के विचार के लिए खतरा पैदा कर दिया है, आजादी के आंदोलन के मूल्य हमारे संविधान में अभिव्यक्त हुए, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने पर आधारित हैं और इसके केन्द्र में है समावेशिता। आरएसएस की विचारधारा आजादी के आंदोलन और भारतीय संविधान के मूल्यों के विपरीत है। और वह अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से उसे आगे बढ़ा रहा है।

प्रारंभ में उसने इतिहास को तोड़-मरोड़कर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की, जैसा इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है जहां औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना सत्ताधारी भाजपा की पहली प्राथमिकता बन गया है। इस समय उसके इशारे पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी भी हैं, जिनके बारे में यह प्रोपेंडो फैलाया जा रहा है कि हमें आजादी दिलवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यहां तक कि उसके कई सोशल मीडिया पोस्ट्स पर यह तक दावा किया जा रहा है कि गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में रोड़े अटकाने का काम किया।

यह सूची बहुत लंबी है। आज क्या किए जाने की जरूरत है? करात का यह कहना सही है कि एक वृहद धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाए जाने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस यात्रा का पहला कदम था। जरूरत इस बात की है कि इस गठबंधन को और सशक्त बनाया जाए। गठबंधन के आंतरिक मतभेदों, टकरावों और विवादों को सुलझाया जाए। गठबंधन के सदस्य दलों के बीच कुछ विरोधाभासों के बावजूद 10 लाख से अधिक सदस्यों वाली करात की पार्टी इस गठबंधन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए घटक दलों को छोटी-छोटी कुर्बानियां देनी ही होंगी।

इस प्रक्रिया का ओर बल प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों को वह प्रभावी काम जारी रखना होगा जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया था। एक राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष गठबंधन भी इन्हें शुरू कर सकता है। वर्तमान सत्ताधारियों का ठीक-ठीक चरित्र फासीवादी हो या उसमें फासीवाद के कुछ तत्व हों या जो भी हो, इंडिया की रणनीति एक व्यापक गठबंधन बनाने की होनी चाहिए जो उस ऊर्जा और गतिशीलता से भरा हुआ हो, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नजर आई थी।

ज्यादा हैं। भारत के गलत आंकड़ों की वजह से इस रोग का विश्वस्तरीय आकलन सही ढंग से नहीं हो पाया है। पिछले कुछ समय से टीबी के कई नए रूप सामने आ गए हैं। कई मानसिक बीमारियां टीबी का बड़ा कारण बनकर उभरी हैं। इस बीमारी को लेकर हमें नजरिया बदलने की जरूरत है। सरकार को परम्परागत तौर-तरीके से बाहर निकलना होगा। टीबी से निपटने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के

साथ मिलकर व्यापक योजना बनानी होगी। टीबी का संबंध पोषण से जुड़ा रहता है। भूखे पेट रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए टीबी की बीमारी के शिकार गरीब तबके के लोग ज्यादा होते हैं। पोषण से मतलब संतुलित भोजन से माना जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर केवल टीबी का इलाज मुहैया करा भर देने से टीबी का खात्मा संभव नहीं है। यह तब मुमकिन होग जबकि देश में लोगों को रोग प्रतिरोधक ताकत

बनाए रखने के लिए संतुलित आहार भी मिले।  
कुछ वर्षों पूर्व तक टीबी की बीमारी को लाईलाज रोग माना जाता था।

लाइलाज रोग माना जाता था। टीबी के मरीजों को घर से अलग रखा जाता था व उससे अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। मगर अब टीबी की बीमारी का देश में पर्याप्त उपचार व दवा उपलब्ध है। टीबी के रोगियों द्वारा नियमित दवा के सेवन से नो माह में ही टीबी का रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। सरकार को टीबी रोग की प्रभावी रोकथाम के लिये बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये और अधिक राशि का प्रावधान करना होगा। टीबी के प्रति लोगों को सचेत करने के लिये देश भर में टीबी जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर ही टीबी पर काबू पाया जा सकता है।



इलाज चल रहा है उन्हें सरकार छारा 500 रुपए प्रतिमाह नगद सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। टी.बी माइक्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया फेफड़ों में उत्तर होकर उसमें धाव कर देते हैं। यह कीटाणु फेफड़ों, त्वचा, जोड़ों, मेरुदण्ड, कण्ठ, हड्डियों, अंतडियों आदि पर हमला कर सकते हैं। दुनिया में छ्ह-सात करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और हर वर्ष 25 से 30 लाख लोगों की इससे मौत हो जाती है। दुनिया में बीमरियों से मौत के 10 शीर्ष कारणों में दीरी तरे पापात तृष्णा पापा है।

टाबा का प्रमुख बताया गया है।  
एक अनुमान के मुताबिक भारत में रोजाना करीब आठ सौ लोगों को मौत टीबी की वजह से हो जाती है। भारत में टीबी के करीब 10 प्रतिशत मामले बच्चों में हैं। लेकिन इसमें से केवल छह







